Krishi Kumbh
Online E-Magazine
Www.KrishiKumbh.Com

कृषि कुंभ

E-ISSN: 2582-9769

कृषि कुंभ
हिंदी मासिक पत्रिका

खण्ड 04 भाग 05, (अक्टुबर, 2024)
पृष्ठ संख्या 01–02

भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका

मनोज कुमार[1], मोहित कुमार पाण्डेय[1], शुभम सिंह[1], ऋषभ यादव[1] एवं ज्ञानेन्द्र सिंह[2]

[1]शोध छात्र, कृषि प्रसार व संचार विभाग,
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एंव प्रौधोगिकी विश्वविद्यालय मेरठ
[2]परास्नातक छात्र, कृषि प्रसार व संचार विभाग,
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एंव प्रौधोगिकी विश्वविद्यालय मेरठ, भारत।

Email Id: –pramodjangirghanau@gmail.com

परिचय

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, भारत की सकल धरेलु आय मे कृषि का एक महत्वपूर्ण योगदान है एवं कृषि देश की समग्र सामाजिक आर्थिक संरचना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लगभग 70–75 प्रतिशत ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं, देश में 82 प्रतिशत किसान परिवार सीमांत व लधु किसानों से संबंध रखते हैं, अतः खेती इन परिवारों के लिए सिर्फ एक व्यवसाय नहीं है, बल्कि अपनी जीविका चलाने का एक साधन भी है जिसमें बच्चों सहित परिवार के सभी सदस्य किसी न किसी तरह से अपना योगदान देते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मान्यता

अंतर्राष्ट्रीय विकास समुदाय का मानना है कि कृषि उन देशों में विकास हेतु व गरीबी के उन्मूलन्म का अच्छा साधन है जिस देश मे कृषि गरीबों का मुख्य व्यवसाय होता है, कृषि क्षेत्र के विकास में महिलाओं की अहम भूमिका होती है। महिलाएं विभिन्न कृषि कार्यों में सक्रिय भागीदार हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार, कृषि मजदूरों मे सभी महिला प्राथमिक श्रमिकों का 55 प्रतिशत हिस्सा है, जबकि कृषकों की हिस्सेदारी मे 24 प्रतिशत है। ग्रामीण महिलाएं भारत सहित अधिकांश विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक मानी जाती हैं। ग्रामीण महिलाएं अपने घरों के प्रबंधन व आजीविका को चलाने के लिए कई गतिविधियां व नितियां को अपनाती हैं। उनकी इन गतिविधियों में कृषि फसलों का उत्पादन, जानवरों की देखभाल, संग्रहण, भोजन पकाना, कृषि या अन्य ग्रामीण उद्यमों में मजदूरी करना, ईंधन और पानी इकट्ठा करना, व्यापार और विपणन (अपने उत्पाद को बेचना), और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना इत्यादि शामिल है। परंतु उल्लेखित कई गतिविधियों को अधिकारिक रिकार्ड में ''आर्थिक रूप से सक्रिय रोजगार'' के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन के अनुसार, सर्वप्रथम महिलाओ ने ही पौधो की देखभाल व उन्हे उगाना सीखा था जहां पुरुष भोजन की तलाश मे शिकार करने जंगल जाते थे, वहीं महिलाओ ने पौधो से बीज इकठ्ठा करना शुरू किया और उन बीजो से खेती करना शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने लिए भोजन, अपने जानवरों के लिए भोजन, कपड़ों के लिए फाइबर और आग जलाने के लिए लकड़ी प्राप्त की।

समकालीन संदर्भ

वर्तमान समय मे बढ़ती हुई आबादी व गावों मे पर्याप्त रोजगार की सुविधा न होने से यह देखा जा रहा है कि अधिकतर पुरुष रोजगार कि तलाश मे गावों से पलायन करके शहरों की ओर जा रहे है जिस कारण महिलाओ पर कृषि संबन्धित अधिकतर कार्य की जिम्मेदारी होती जा रही है।

परंतु ग्रामीण इलाको मे अभी भी यह देखा जा रहा है कि महिलाओ को कृषि संबन्धित निर्णय जैसे खेत मे कौन–सी फसल लगानी है, कब– कब खाद व पानी देना है तथा कब और कौन–सी कीटनाशक का प्रयोग कारना है आदि के लिए पुरुषो पर निर्भर रहना पड़ता है, निर्णय संबन्धित अधिकतर हिस्सेदारी पुरुषों के पास होती है। परिवर्तनीय वातावरण कारणवश निर्णय संबन्धित हिस्सेदारी धीरे– धीरे महिलाओं का बढ़ रहा हैं।

महिलाओं की बहु–आयामी भूमिका

कृषिगत गतिविधियाँ: बुवाई, रोपाई, निराई, सिंचाई, उर्वरक अनुप्रयोग, पौध संरक्षण, कटाई, विनिंग, भंडारण आदि।

घरेलू गतिविधियाँ: खाना पकाने, बच्चे का पालन, पानी संग्रह, ईंधन लकड़ी इकट्ठा करना, घरेलू रखरखाव आदि।

संबद्ध गतिविधियाँ: मवेशी प्रबंधन, चारा संग्रह, दूध निकालना आदि।

सरकारी प्रयास और नीतियाँ

भारत में, महिलाओं के समग्र विकास, सामाजिक–आर्थिक और स्वास्थ्य सुरक्षा को सशक्त बनाने के लिए कई सुधारों को रेखांकित किया गया है। आजादी के बाद से, रोजगार के अवसर प्रदान करके और भुगतान की गई नौकरियों में महिलाओं के सहभागिता में सुधार के लिए कई सरकारी प्रमुख योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इनमे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP), राष्ट्रीय आजीविका मिशन, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (DDU-GKY), प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आदि जैसी विभिन्न योजनाएं वर्तमान मे सरकार द्वारा चला रही हैं। उपरोक्त विभिन्न योजनाएं ने भारत में लैंगिक समानता और महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

वर्तमान प्रगति

वर्तमान समय में, ग्रामीण महिलाओं को सरकारी योजनाओं के माध्यम से शिक्षा, उत्पादक संसाधनों, क्षमता निर्माण, कौशल विकास, स्वास्थ्य संबन्धित सुविधाओं और विविध आजीविका के अवसरों का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुसार, भारत सरकार ने कृषि और संबद्ध क्षेत्र में संलग्न ग्रामीण महिलाओं को संसाधन और योजनाओं को प्रदान करने के लिए कृषि में लैंगिक मुख्यधारा के एजेंडा (विषय) को प्राथमिकता दी है। ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी को मुख्यधारा में लाने के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा विशेष लाभार्थी–केंद्रित योजनाएं चलायी जा रही हैं। इन विशेष योजनाओं में ो महिला किसानों के लिये कम से कम 30 प्रतिशत व्यय का प्रावधान है।

प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम

महिला किसानों के बीच कौशल विकास और क्षमता निर्माण के लिए, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं के तहत विभिन्न प्रकार के कौशल–प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजिम किए जा रहे हैं। इनमें कृषि विस्तार उप मिशन के अंतर्गत विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को सहायता शामिल है। देश भर में राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थानों, राज्य कृषि प्रबंधन और विस्तार प्रशिक्षण (SAMETI), कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs) और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (SAUs) के माध्यम से महिला किसानों के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों (न्यूनतम 200 घंटे की अवधि) में कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं।